हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 2022 को माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

माननीय राज्यपाल का अभिभाषण

राष्ट्रगान गाया गया।

23-02-2022/1100/एन.जी.-जे.एस./ए.जी.-ए.एस./1

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

1. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभालने के पश्चात पहली बार माननीय सदन के इस वर्ष के प्रथम सत्र तथा हिमाचल प्रदेश की तेरहवीं विधान सभा के चौदहवें सत्र को सम्बोधित करते हुए, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं, आप सभी माननीय सदस्यों तथा आपके माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के समापन पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं।
2. माननीय सदन के इस अधिवेशन का आयोजन वर्ष 2021–22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें पारित करने, वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान पारित करने तथा महत्वपूर्ण विधायी कार्य के लिए किया गया है। जैसे कि इस सदन की परम्परा रही है, मुझे आशा है कि आप अपने अनुभव और जनहित की प्रतिबद्धता के माध्यम से विचार–विमर्श के स्तर को और ऊंचा उठायेंगे।
3. मेरी सरकार पिछले लगभग दो वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड–19) के कारण उत्पन्न विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए **'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना'** एवं **'आत्मनिर्भर भारत अभियान'** तथा अन्य जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवाई गई सभी प्रकार की आर्थिक सहायता हेतु केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करती है। इस महामारी की चपेट में आए व्यक्तियों को समय पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 3 अस्थाई अस्पताल बनाए गए। **जहां पहले प्रदेश में केवल दो PSA plants कार्यरत थे, अब उसकी तुलना में 48 PSA plants का निर्माण किया गया है। इससे 90 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अतिरिक्त तौर**

पर उपलब्ध होगी। पहले जहां प्रदेश में 52 Ventilators उपलब्ध थे, अब 1,014 Ventilators प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में कार्यशील हैं। इसी तरह ICU Beds की उपलब्धता 52 से 557 कर दी गई है। 3,000 की तुलना में अब प्रदेश में लगभग 17,000 Oxygen Cylinders/ Concentrators उपलब्ध हैं।

4. जैसा कि सर्वविदित है, इस महामारी से निपटने के लिए देशभर में यशस्वी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारा प्रदेश उनके मार्गदर्शन, frontline workers के अथक प्रयासों और जनता के सहयोग से इस **टीकाकरण की पहली व दूसरी डोज के शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने में देश का सबसे पहला प्रदेश बना। स्वयं प्रधान मंत्री ने हिमाचल प्रदेश की इस उपलब्धि की सराहना की।**

5. **'सेवा और सिद्धि के चार साल समृद्धि के'** मेरी सरकार ने इन चार वर्षों में प्रदेश को नए शिखर तक पहुंचाने, आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने, युवाओं के लिए रोज़गार और स्वावलम्बन के द्वार खोलने, महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक उत्थान, किसानों एवं बागवानों की खुशहाली तथा समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाने की दिशा में अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं। इनसे प्रदेशवासियों को अपने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अपार अवसर प्राप्त हो रहे हैं तथा उनका आत्मसम्मान और आत्मगौरव बढ़ा है।

6. किसानों की आय को दोगुना करने तथा कम लागत की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना'** आरम्भ की गई है। अब तक 1 लाख 60 हज़ार किसानों ने केमिकलों का उपयोग छोड़कर प्राकृतिक खेती को सफलतापूर्वक अपनाया है और 23 हज़ार एकड़ भूमि इस योजना के अन्तर्गत लाई गई

है। प्राकृतिक खेती को अपनाने से किसानों को विभिन्न फसलों के उत्पादन पर होने वाली लागत में 26 से 56 प्रतिशत की कमी और शुद्ध आय में 11.8 प्रतिशत से 63.6 प्रतिशत तक की वृद्धि पाई गई है। इन प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी सराहना की गई है और उन्होंने पूरे देश के किसानों से इस खेती को अपनाने का आह्वान किया है। बंदरों और अन्य जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को संरक्षित करने के लिए आरम्भ की गई **'मुख्यमन्त्री खेत संरक्षण योजना'** के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रूपयों की धनराशि व्यय की गई है, जिससे 1 हज़ार 350 किसान लाभान्वित हुए हैं।

7. केसर व हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए **'कृषि से सम्पन्नता योजना'** राज्य के 06 जिलों, चम्बा, मण्डी, कांगड़ा, कूल्लू, लाहौल–स्पीति तथा किन्नौर में आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत केसर की खेती के लिए 10 हज़ार वर्गमीटर एवं हींग की खेती के लिए 30 हज़ार वर्गमीटर का क्षेत्रफल लाया गया है।

8. प्रदेश के किसानों एवं उत्पादकों को उनकी उपज के विपणन हेतु समुचित सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मंडियां सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। प्रदेश में तीन नई मंडियों– मेहंदली, शिलारू और बन्दरोल में लगभग 37 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है। 20 नई मंडियों को e-NAM के अन्तर्गत लाने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है। शीघ्र ही ये मंडियां 19 अन्य मंडियों के साथ e-NAM पोर्टल से जुड़ जाएंगी। फूलों की खेती को Himachal PradeshAgricultural Horticultural Produce Marketing (DevelopmentAnd Regulation)Act, 2005 के Schedule में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, 22 Market Yards के विस्तार एवं आधुनिकीकरण का कार्य पूरा कर दिया गया है।

9. राज्य में कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि हेतु जल संरक्षण एवं आश्वस्त सिंचाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **'जल से कृषि को बल योजना'** आरम्भ की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 297 water harvesting structures का निर्माण किया गया है, जिससे 21 हज़ार 701 square मीटर जल भण्डारण क्षमता विकसित हुई है। इस कार्य पर 83 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि व्यय कर लगभग 404 हेक्टेयर क्षेत्र इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

10. मेरी सरकार ने प्रदेश में आधुनिक मशीनरी एवं उपकरणों से खेती को बढ़ावा देने के लिए **'राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम'** आरम्भ किया है। चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि व्यय कर 25 हज़ार 953 आधुनिक मशीनरी एवं कृषि उपकरण प्रदेश के किसानों एवं बागवानों को उपलब्ध करवाए गए हैं।

11. मेरी सरकार बागवानी क्षेत्र के विस्तार एवं समग्र विकास हेतु निरन्तर प्रयासरत है। वर्तमान में बागवानी का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का योगदान है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का लगभग 1 हज़ार 932 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र, विविध फल फसलों के अन्तर्गत लाया गया है। बागवानों को सेब का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु **'मण्डी मध्यस्थता योजना'** के अन्तर्गत, लगभग 69 करोड़ 56 लाख रुपये मूल्य के 'सी–श्रेणी' का 73 हज़ार 217 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई।

12. प्रदेश में बागवानी के समग्र विकास में **'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना'** महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 2,927 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, फल पौधों के कीट संरक्षण हेतु **'पौध संरक्षण कार्यक्रम'** चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बागवानों को temperate फलों के लिए pesticides की खरीद

पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 4 हज़ार रुपये प्रति हैक्टेयर तथा subtropical फलों के लिए pesticides की खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 2 हज़ार रुपये प्रति हैक्टेयर की सहायता प्रदान की जा रही है।

13. वर्तमान में प्रदेश में 548 फल पौधशालाएं पंजीकृत हैं। चालू वित्त वर्ष में 150 नई फल पौधशालाओं तथा 158 बड–वुड बैंकों को पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, लगभग 235 हैक्टेयर क्षेत्र को Bio Control के अन्तर्गत लाया गया है जिससे 245 बागवान व किसान लाभान्वित हुए हैं।

14. **'हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना'** के अन्तर्गत लगभग 11 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। इस योजना से 114 बागवान लाभान्वित हुए हैं और लगभग 58 हज़ार 561 वर्ग मीटर का अतिरिक्त क्षेत्र polyhouses के अन्तर्गत लाया गया है। इसके अतिरिक्त **'हिमाचल खुम्ब विकास योजना'** के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है, जिससे वर्तमान में 269 मशरूम उत्पादकों को खुम्ब उत्पादन इकाइयों की स्थापना हेतु लाभान्वित किया गया है।

15. मेरी सरकार द्वारा बागवानी के दीर्घकालिक विकास हेतु सुधरी फल किस्मों एवं clonal rootstock का आयात करके उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। विश्व बैंक पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अन्तर्गत इस वर्ष में हुई प्रगति की विश्व बैंक द्वारा भी प्रशंसा की गई है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2021–22 के दौरान अमेरिका से विभिन्न temperate फलों के 9,09,527 grafted plants और clonal root stocks आयात किए हैं, जिनका multiplication कर प्रदेश के बागवानों को वितरित किया जाएगा।

16. राज्य में ओलावृष्टि से बगीचों में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए Anti-hail nets लगाने हेतु स्टील व बांस से निर्मित स्थाई ढांचों के

लिए **'कृषि उत्पाद संरक्षण योजना'** आरम्भ की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। अब तक लगभग 666 हैक्टेयर क्षेत्र इसके अन्तर्गत लाया गया है और 2315 किसान लाभान्वित हुए हैं।

17. मेरी सरकार गौ सेवा के प्रति समर्पित है। इसके लिए ताल, जिला हमीरपुर एवं ज्योरी, जिला शिमला स्थित भेड़ प्रजनन फार्म तथा पालमपुर, जिला कांगड़ा एवं बागथन, जिला सिरमौर स्थित गाय प्रजनन फार्मों को चारा उत्पादन केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया है। जिन पर 3 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। इसके अतिरिक्त, पशुओं की उचित देखभाल हेतु 4 पशु अभ्यारण्य/बड़े गौ सदन लूथान व खाबल, जिला कांगड़ा, खेरी, जिला हमीरपुर तथा सुन्नी, जिला शिमला में लगभग 9 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से स्थापित किए गए हैं।

18. प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पशुपालन का अहम योगदान है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पशुपालकों को उच्च श्रेणी की विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य के 3 जोनल अस्पतालों और 10 वैटरीनरी पॉलीक्लिनिक में आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। इसके अतिरिक्त, जिला कांगड़ा के पशु औषधालय सिंहूड़, को पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत किया गया है तथा जिला चम्बा के अघार में नया पशु औषधालय भी खोला गया है।

19. **'राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम'** के अन्तर्गत प्रदेश में 2 लाख 92 हज़ार पशुओं का गर्भाधान करने हेतु 15 करोड़ 83 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। इसके अतिरिक्त, जिला ऊना के बसाल में Centre of Excellence की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 12 करोड़ 92 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है।

20. प्रदेश के लगभग 13 हज़ार से अधिक परिवार मछली पकड़ने व पालने का कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं को स्वरोज़गार प्रदान करने की अपार सम्भावनाएं है। मेरी सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में लगभग 537 युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित **'प्रधानमन्त्री मत्स्य संपदा योजना'** के अन्तर्गत लगभग 49 करोड़ 50 लाख रुपये की विभिन्न परियोजनाएं भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई हैं।

21. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में 'मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए, सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण सम्बन्धी सहायता' के अन्तर्गत 4208 मछुआरों को 4500 रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, **'ट्राउट पशुधन बीमा योजना'** के अन्तर्गत 24 ट्राउट इकाइयों को बीमा कवर प्रदान किया गया है।

22. राज्य के किसानों व अन्य कमज़ोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने व अतिरिक्त आय के अवसर सृजित करने हेतु सहकारी सभाओं के गठन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न प्रकार की 4849 सहकारी सभाएं ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सोलन व मण्डी जिलों में द्वितीय चरण की एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। 57 करोड़ 19 लाख रुपये की राशि पात्र सहकारी सभाओं को गोदामों के लिए प्रदान की गई है।

23. राज्य के किसानों की आर्थिकी को सुधारने हेतु **'मनरेगा'** को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 891 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और

अब तक 6,22,218 परिवारों ने 2,71,36,000 कार्य–दिवस अर्जित किए हैं। इनमें से 62 प्रतिशत कार्य–दिवस महिलाओं द्वारा अर्जित किए गए हैं। मनरेगा के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 66,498 कार्य पूर्ण किए गए हैं। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्यान्वित की जा रही अन्य विभागीय योजनाओं के साथ मनरेगा की Convergence सुनिश्चित करने के प्रयास सफल रहें हैं। **इसके फलस्वरूप जहां इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 से पहले औसतन 500–550 करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय किए जा रहे थे, वहीं वर्ष 2018–19 से प्रति वर्ष औसतन 850 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं।** चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 1,100 करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान है।

24. चालू वित्तीय वर्ष में **'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)'** के अन्तर्गत 31 करोड़ 88 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। 178 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है। 445 गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियां आरंभ की गई हैं तथा 121 गांवों में तरल कचरा प्रबंधन के तहत कार्य प्रगति पर है।

25. मेरी सरकार द्वारा गरीब परिवारों को, गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए, आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में **'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन'** के अन्तर्गत 6,141 स्वयं सहायता समूहों तथा 320 ग्राम संगठनों का गठन किया गया। इस वर्ष 6,895 स्वयं सहायता समूहों को लगभग 11 करोड़ 23 लाख रुपये का revolving fund तथा 202 ग्राम संगठनों को लगभग 4 करोड़ 46 लाख रुपये की सामुदायिक निवेश राशि प्रदान की गई।

26. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बेघर लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु **'प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण'** के अन्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक 1,670 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई। **'मुख्यमन्त्री आवास योजना'** के अन्तर्गत

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में लगभग 20 करोड़ 93 लाख रुपये की लागत से 1,257 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, **'मातृ–शक्ति बीमा योजना'** के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2021 तक कुल 103 परिवारों को 2 करोड़ 6 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

27. मेरी सरकार ने जनता की शिकायतों का मौके पर समाधान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम **'जनमंच'** आरम्भ किया है। इसके अन्तर्गत राज्य के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में जनवरी से दिसम्बर, 2021 तक 31 जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए। **इस कार्यक्रम के आरम्भ से दिसम्बर, 2021 तक प्रदेश भर में 242 जनमंच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 51, 461 शिकायतें व मांगें प्राप्त हुई जिनमें से 48,478 शिकायतों एवं मांगों का निपटारा कर दिया गया है।**

28. मेरी सरकार जमीनी स्तर पर लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत दिसम्बर माह तक पंचायती राज संस्थाओं को 158 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, 412 नवगठित ग्राम पंचायतों में से 183 ग्राम पंचायतों को नए पंचायत घर के निर्माण हेतु 20 करोड़ 49 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

29. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में **'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान'** के अन्तर्गत 164 करोड़ 43 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि में से 389 कॉमन सर्विस सेंटर व 97 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 32 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय प्रबन्धन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सभी वित्तीय लेनदेन **'ई–ग्राम स्वराज पोर्टल'** के माध्यम से किए जा रहे हैं।

30. राज्य में वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रति वर्ष पौधारोपण अभियान चलाया जाता है। **चालू वित्तीय वर्ष में इस अभियान के अन्तर्गत 13 हज़ार हैक्टेयर वन भूमि में लगभग 1 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।** इसके अतिरिक्त, पूर्ण राज्य की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में आम जनता को वनों के महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूक करने, नगरीय क्षेत्र में वनावरण को बढ़ावा देने तथा मनोरंजन स्थलों को विकसित करने हेतु 68 स्वर्ण वाटिकाएं विकसित की गई हैं।

31. मेरी सरकार द्वारा राज्य में जल संरक्षण हेतु **'जल भण्डारण योजना'** का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 125 चयनित स्थलों पर 25 करोड़ रुपये की लागत से जलाशय निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

32. जहां प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न विभागों द्वारा अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, वहीं मेरी सरकार शहरी स्थानीय निकायों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और इन्हें अपने दायित्वों के निर्वाहन में सक्षम बनाने के प्रति संकल्पबद्ध है। स्तरोन्नत किए गए 03 नगर निगमों को 1 करोड़ रुपये प्रत्येक तथा नव–गठित हर नगर पंचायत व नगर परिषद को 10 लाख रुपये की दर से कार्यात्मक अनुदान राशि प्रदान की गई है।

33. शहरी क्षेत्र में Street vendors को जीवन यापन में मदद करने के उद्देश्य से **'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना'** आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 3,663 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 3,436 लाभार्थियों को 3 करोड़ 64 लाख रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। प्रदेश ने इस योजना को लागू करने में उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्य की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

34. कोविड–19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों के श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा मेरी सरकार की प्राथमिकता है। शहरी

क्षेत्र के श्रमिकों को 120 दिनों का गारंटिड मज़दूरी रोज़गार उपलब्ध करवाने हेतु '**मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना**' आरम्भ की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 01,01,830 कार्यदिवस सृजित किए गए हैं और 3 करोड़ 5 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

35. मेरी सरकार द्वारा शहरी निकायों को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से अश्विनी खड्ड और टूटू में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, लालपानी में फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण व मल्याणा, ढ़ली और लालपानी स्थित प्लांट का उन्नयन किया जा रहा है। इनके निर्माण एवं उन्नयन हेतु अब तक 92 करोड़ 19 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है।

36. वर्तमान वित्तीय वर्ष में '**हिमुडा**' के माध्यम से 159 फ्लैट, 11 मकान व 180 रिहायशी प्लॉट विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिसम्बर माह तक 33 करोड़ 92 लाख रुपये की राशि व्यय कर 80 फ्लैट व 61 रिहायशी प्लॉट विकसित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आम जनता, प्रमोटरों और रीयल इस्टेट की सुविधा हेतु एक सरल पारदर्शी उपभोक्ता केन्द्रित वेब पोर्टल भी आरम्भ किया गया है।

37. सरलीकरण की कड़ी में नगर एवं ग्राम योजना नियमों में संशोधन कर निजी भवन निर्माण में सेट–बैक, floors और भवन की ऊंचाई आदि में छूट का प्रावधान किया गया है।

38. हिमाचल प्रदेश में औद्योगीकरण को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरी सरकार ने प्रदेश को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने, निवेश आमंत्रित करने, युवाओं के लिए रोज़गार सृजित करने के उद्देश्य से कांगड़ा जिला के धर्मशाला में 2019 में '**प्रथम निवेषक सम्मेलन**' का आयोजन किया था। इसके पश्चात् शिमला में आयोजित पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 13,488 करोड़ रुपये के निवेश धरातल पर उतारे गए। मेरी सरकार द्वारा **27 दिसम्बर, 2021 को 04 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के अवसर पर**

देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में मण्डी में द्वितीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। जिसमें 287 परियोजनाओं पर 28,197 करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारा गया।

39. मेरी सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु मूलभूत ढ़ांचे को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। **जिला सोलन के नालागढ़ में 'मैडिकल डिवाइस पार्क' स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और ज़िला ऊना में 'बल्क ड्रग फार्मा पार्क' की स्वीकृति हेतु मेरी सरकार आशान्वित है।**

40. प्रदेश में युवाओं के स्वावलम्बन के लिए आरम्भ **'मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना'** काफी लोकप्रिय हुई है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 85 करोड़ रुपये की अनुदान राशि वितरित कर 2,231 इकाइयां स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार ने राज्य एकल खिड़की अनुश्रवण व समाधान प्राधिकरण के माध्यम से गत वर्ष लगभग 9,415 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की 39 नई व 33 वर्तमान परियोजनाओं के विस्तारीकरण की स्वीकृति प्रदान की, जिनमें 16,669 व्यक्तियों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे।

41. मेरी सरकार श्रमिकों एवं कामगारों के हितों की रक्षा हेतु कृतसंकल्प है। 01 अप्रैल, 2021 से अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए मज़दूरी की न्यूनतम दर को **275 रुपये से बढ़ाकर 300 रूपए प्रतिदिन** किया गया है।

42. मेरी सरकार ने 'BuildingAnd other Construction Workers Welfare Board' के पंजीकृत कामगारों के लिए चालू वित्त वर्ष में विभिन्न कल्याणकारी योजनायें शुरू की हैं जैसे बेटी के जन्म पर उपहार सहायता के लिए 51,000 रुपये, मानसिक रूप से मंद/अपंग बच्चों की सहायता के लिए प्रति वर्ष 20,000 रुपये, विधवा पैंशन के लिए 1,500

रुपये प्रतिमाह और आवास एवं शिक्षा के लिए सहायता राशि। इसके अन्तर्गत 60 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं। **इसके अतिरिक्त, 31 दिसम्बर, 2021 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 8 लाख श्रमिकों का ई–श्रम पोर्टल के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया है।**

43. असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ की गई **'प्रधान मन्त्री श्रम योगी मान–धन पेंशन योजना'** के अर्न्तगत 60 वर्ष या इससे अधिक की आयु के व्यक्ति को 3000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को पेंशन का 50 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 42,76 कामगारों को पंजीकृत किया गया है।

44. चालू वित्तीय वर्ष में **'कौशल विकास भत्ता योजना'** के अन्तर्गत 38,275 लाभार्थियों को 17 करोड़ 68 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त, **'औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना'** के अन्तर्गत 2,532 अभ्यर्थियों को 1 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि औद्योगिक विकास भत्ते के रूप में प्रदान की गई है।

45. मेरी सरकार द्वारा **'बेरोज़गारी भत्ता योजना'** के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 66,280 लाभार्थियों को 39 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।

46. मेरी सरकार राज्य में जल विद्युत के उचित दोहन के साथ ऊर्जा का सही उपयोग करने हेतु कृतसंकल्प है। प्रदेश की पाँच नदियों से कुल 24,567 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता विद्यमान है। इसमें से लगभग 10,948 मेगावाट क्षमता का दोहन कर लिया गया है तथा शेष 13,619 मेगावाट में से अधिक से अधिक क्षमता का दोहन 2030 तक कर लिया जाएगा।

47. मेरी सरकार ने आज के परिदृश्य में ऊर्जा दोहन, संचारण व वितरण के क्षेत्र में आए बदलावों और प्रदेश में विद्यमान स्रोतों से ऊर्जा का शीघ्र दोहन करने के उद्देश्य से '**स्वर्ण ऊर्जा नीति 2021**' पारित की है और **एक Vision Document, 2030** भी तैयार किया है। **इसके अन्तर्गत वर्ष 2030 तक 10 हज़ार मेगावॉट अतिरिक्त हरित ऊर्जा का उत्पादन करना, प्रदेश को hydro battery राज्य के रूप में विकसित करना, शत–प्रतिशत हरित ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित करना, ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा देना, औद्योगिक उत्पाद में शत–प्रतिशत हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए Single Window Clearance System स्थापित करना और Pump Storage परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन देना आदि शामिल है।** इसके फलस्वरूप लगभग 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश, 1 लाख लोगों को रोज़गार तथा विद्युत के विक्रय से लगभग 4 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा।

48. प्रदेश में चौबीस घंटे विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करवाना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 55 EHV सब–स्टेशनों, 209, 33 KV सब–स्टेशनों, 3,615 किलोमीटर EHV Transmission लाइनों एवं 01,01,801 किलोमीटर HT/LT लाइनों का एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित किया गया है।

49. मेरी सरकार राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कम वोल्टेज़ की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से एक योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसके प्रथम चरण में लगभग 158 करोड़ रुपये लागत से नवम्बर, 2021 तक 917 वितरण उप–केन्द्रों के साथ–साथ 575 किलोमीटर HT व 365 किलोमीटर LT लाइनों का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 101 किलोमीटर सिंगल फेज़ LT लाइनों को थ्री फेज़ में परिवर्तित किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में पांगी तथा

लाहौल–स्पिति में 1,500 सोलर off-grid संयन्त्र BPL परिवारों को उपलब्ध करवाए गए हैं। इन पर लगभग 5 करोड़ 66 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

50. भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आबंटित 40 मेगावाट की **'रेणुकाजी बांध परियोजना'** को **'राष्ट्रीय महत्व'** की परियोजना घोषित किया गया है। केन्द्र सरकार ने इस परियोजना हेतु लगभग 7 हज़ार करोड़ रुपये की संशोधित लागत स्वीकृत की है। **'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना'–'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम'** के अन्तर्गत वित्त पोषित इस परियोजना की आधारशिला 27 दिसम्बर, 2021 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा रखी गई।

51. प्रदेश में ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु राज्य सरकार, एशियाई विकास बैंक और जर्मन विकास बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सफल रही है। वर्तमान में एच0पी0पी0टी0सी0एल0 द्वारा 106 करोड़ रुपये की लागत से 2 ट्रांसमिशन लाइनें चालू की गई हैं। इससे मौजूदा राज्य ट्रांसमिशन नेटवर्क में 73 सर्किट किलोमीटर जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त, 205 सर्किट किलोमीटर लंबाई की 5 ट्रांसमिशन लाइनों, 651 M.V.A परिवर्तन क्षमता वाले 6 E.H.V सब–स्टेशनों का कार्य प्रगति पर है, जिसे 556 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से 31 मार्च, 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।

52. प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार के सौजन्य से चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना **'जल जीवन मिशन'** के अन्तर्गत राज्य के **'हर घर को नल से जल'** पहुंचाने के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इस योजना के अन्तर्गत कुल 17 लाख 28 हज़ार परिवारों में से 15 लाख 89 हज़ार परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने 01,262,68 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की है। हिमाचल

प्रदेश पूरे देश में fourth tranche प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। **गौर करने की बात है कि पिछले 72 वर्षों में प्रदेश में लगभग 07, 63,000 नल कनेक्शन लगाए गए जबकि इसकी तुलना में पिछले 2 वर्षों में लगभग 08,35,000 नल कनेक्शन लगाए गए हैं।** इसके अतिरिक्त, सुरक्षित पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 58 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनमें से 37 प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता प्राप्त है।

53. ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जलापूर्ति सुविधा सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 740 करोड़ रुपये की लागत से 24 योजनाओं की एक परियोजना के वित्त पोषण हेतु न्यू डवलपमेंट बैंक से स्वीकृति प्राप्त की गई है तथा समझौते पर हस्ताक्षर उपरान्त लगभग 350 करोड़ रुपये की लागत की योजनाओं पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता एवं संचालित योजनाओं में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं के 15,166 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

कांग्रेस विधायक दल ने इसे झूठ का पुलिंदा कहते हुए सदन से बहिगर्मन किया।

54. मेरी सरकार द्वारा लाहौल–स्पिति के केलांग शहर में lnti-freeze जलापूर्ति प्रणाली स्थापित करने हेतु जनजातीय क्षेत्र उप–योजना के अन्तर्गत लगभग 13 करोड़ 69 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

55. एक पहल के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज योजनाओं के संचालन हेतु प्रदेश सरकार ने 15 योजनाओं को नाबार्ड से, विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत वित्त पोषण के लिए शामिल किया है। इनमें से 12 योजनाओं की DPR नाबार्ड को भेजी जा चुकी है।

56. मेरी सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में जल रक्षक का मानदेय बढ़ाकर **3,600 रुपये** तथा पैरा पंप ऑपरेटर व पैरा फिटर का मानदेय बढ़ाकर **4,600 रुपये प्रतिमाह** कर दिया है।

57. हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य की अर्थव्यवस्था में सड़कों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। रेल व हवाई यातायात के सीमित साधनों के कारण यहां सड़कों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। राज्य में वर्तमान में 39,060 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कें हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 37 गांवों को वाहन योग्य सड़कों से जोड़ने का कार्य पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त 560 किलोमीटर नई सड़कों, 1,865 किलोमीटर पक्की सड़कों व 52 पुलों का निर्माण कार्य और 664 किलोमीटर में जल निकास का कार्य पूर्ण किया गया है।

58. मेरी सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 68 सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु नाबार्ड से 516 करोड़ 73 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त की है। '**प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना**' के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में कुल 1,328 किलोमीटर लंबी सड़कों का उन्नयन किया गया है। इसके अतिरिक्त, परवाणू से सोलन (39 कि0मी0 लंबाई), कुल्लू से मनाली (37 कि0मी0 लंबाई) और किरतपुर से नेरचौक के विभिन्न क्षेत्रों में (19 कि0मी0 लंबाई) 4–लेन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

59. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण और विभागीय क्षमता में बढ़ौतरी के लिए मेरी सरकार ने जिला मण्डी के धर्मपुर में नया वृत, जिला सिरमौर के सराहन, जिला कांगड़ा के शाहपुर तथा जिला मण्डी के थलोट में नए मण्डल सृजित किए हैं। इसके अतिरिक्त, जिला सिरमौर के गगल शिकोर व टिंबी तथा जिला कांगड़ा के द्रीणी में नए उप–मण्डल सृजित किए गए हैं।

60. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से राज्य में 2 '**हरित राष्ट्रीय राजमार्ग**' आरम्भ किए गए हैं।

इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग पांवटा साहिब से गुम्मा–फेडिस (95 कि0 मी0 लंबाई) का कार्य आरम्भ हो चुका है और हमीरपुर से मंडी (109 कि0 मी0 लंबाई) के आवंटन की प्रक्रिया जारी है जिसे इस साल जून माह तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

61. **कोरोना महामारी की कठिन परिस्थिति में भी आम नागरिकों को समय पर बस सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को सहायता अनुदान के रूप में लगभग 223 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है।** मेरी सरकार द्वारा जनहित में दिसम्बर माह तक 285 अतिरिक्त रूटों पर बसें चलाई जा रही हैं। 370 बसों के रूट में बढ़ौतरी अथवा परिवर्तन किया गया है, इससे इन बसों द्वारा प्रतिदिन लगभग 42,594 अतिरिक्त किलोमीटर का सफर तय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 205 नई बसें भी खरीदी जा रही हैं।

62. मेरी सरकार द्वारा रोज़गार सृजन के साथ लोगों को गुणात्मक एवम् आरामदायक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए **'स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार (परिवहन) योजना'** आरम्भ की गई है।

63. चालू वित्त वर्ष में विभिन्न श्रेणी के परमिट जारी कर 800 लोगों को अप्रत्यक्ष व 10,018 लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल पथ परिवहन निगम में 359 चालकों व 598 परिचालकों की नियुक्तियां तथा 923 अनुबन्ध कर्मचारियों को नियमित किया गया है।

64. चालू वित्त वर्ष में कुल्लू में Public Private Partnership से नवनिर्मित आधुनिक बस अड्डे को क्रियाशील कर यातायात सुविधा हेतु प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। 07 बस अड्डोंः– अम्ब, निरमंड, कोटखाई, करसोग, नालागढ़, शाहपुर व नाहन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 2 नए बस अड्डों थुनाग व जंजैहली का निर्माण कार्य

प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, संसारपुर टेरस में नया डिपो व जंजैहली में नया सब–डिपो खोला गया है।

65. प्रदेश के ग्रामीण तथा अनछुए स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा युवाओं को स्वरोज़गार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से **'नई राहें नई मंज़िलें योजना'** आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत विगत चार वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। मण्डी (छोटी काशी) में शिवधाम का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में 40 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 12 शिव ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां स्थापित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, बीड़–बिलिंग, कांगड़ा को पैराग्लाइडिंग गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए 8 करोड़ 37 लाख रुपये की राशि व्यय की जा रही है और जिला शिमला के चांशल क्षेत्र को भी इको–टूरिज़्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।

66. राज्य में झीलों की उपलब्धता के दृष्टिगत Water Sports की अपार संभावना है। मेरी सरकार द्वारा तत्तापानी, अन्दरोली (कुटलैहड़), लारजी और पौंग बांध को Water Sports गतिविधियों के लिए विकसित किया जा रहा है। इनमें से तत्तापानी व लारजी में 13 करोड़ 53 लाख रुपये की राशि व्यय कर Water Sports गतिविधियां आरम्भ कर दी गई हैं। पौंग बांध में आधारभूत संरचना के विकास और अन्दरोली (कुटलैहड़) में Water Sports Complex के विकास हेतु लगभग 4 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

67. हिमाचल प्रदेश, देश–विदेश के सैलानियों का पसंदीदा गंतव्य है। अतः आगंतुकों के लिए प्रदेश की संस्कृति, धार्मिक स्थल, साहसिक खेल व स्वच्छ वातावरण आकर्षण का केन्द्र है। मेरी सरकार द्वारा राज्य में ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने के लिए 15 स्थलों की पहचान कर ली गई है, जहां पर्यटकों को सुविधा और स्थानीय लोगों को रोज़गार के

अवसर उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य में साहसिक पर्यटन को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में साइकिल मार्गों को विकसित किया जा रहा है। स्पीति में बड़े पैमाने पर आइस स्केटिंग रिंक विकसित करने का प्रस्ताव भी आमंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, नादौन में राष्ट्रीय राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा चलो चम्बा अभियान के अन्तर्गत तलेरू, चम्बा में Indian KayakingAnd CanoeingAssociation (IKCA) के सहयोग से **'The Himalyan Goral 9th National Dragon Boat Race Championship'** का भी आयोजन किया गया।

68. माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। राज्य सरकार बड़े पैमाने पर पर्यटकों के लिए सोलंग और सिस्सु में पर्यटन गतिविधियों का विकास कर रही है और कुछ बुनियादी पर्यटन गतिविधियों को शुरू किया जा चुका है। नई ए0डी0बी0 परियोजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए अटल सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों और लाहौल और स्पीति जिले में भी पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिए DPR तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त एच0पी0टी0डी0सी0 के 9 होटलों को Destination Wedding Location के रूप में विकसित किया जा रहा है।

69. मेरी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धर्मशाला और मैकलोडगंज में प्रमुख मंदिर परिसरों के संरक्षण और बुनियादी ढांचे के उन्नयन, चामुंडा व ब्रजेश्वरी मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार और सुधार, नगरोटा–बगवां में पारंपरिक शिल्प–कला सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण, मार्कंडेय मंदिर परिसर के कायाकल्प, ज्वाला जी में पार्किंग, नालदेहरा में इको–टूरिज़्म पार्क तथा शिमला मॉल एक्सटेंशन की बहाली का कार्य

165 करोड़ 72 लाख रुपये की लागत से पूरा कर लिया है। इसके अतिरिक्त, धर्मशाला रोपवे आरम्भ हो चुका है।

70. हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। मेरी सरकार ने हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में राज्य की पहली सांस्कृतिक नीति अधिसूचित की है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वित्त वर्ष में शिल्पकारों के प्रोत्साहन हेतु शिमला, चम्बा और दिल्ली में शिल्प मेलों का आयोजन भी किया गया है।

71. मेरी सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में **'आयुष्मान भारत– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना'** सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 4 लाख 25 हज़ार परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जनवरी, 2022 तक इस योजना के अन्तर्गत 01 लाख 23 हज़ार लाभार्थियों को 143 करोड़ 17 लाख रुपये की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

72. जो परिवार आयुष्मान भारत में पात्र नहीं हैं या सरकारी अथवा सेवानिवृत कर्मचारी नहीं हैं, उनके लिए **'मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना'** भी आरम्भ की गई है। **इस योजना के अन्तर्गत 5 लाख 13 हज़ार परिवारों को हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। जनवरी, 2022 तक 2 लाख 27 हज़ार लाभार्थियों को लगभग 201 करोड़ रुपये की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।** इसके अतिरिक्त, **'मुख्यमन्त्री निशुल्क दवाई योजना'** के बजट में 30 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। मेरी सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक 56 लैब टैस्ट की निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और हर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 236 टैस्ट करने की सुविधा होगी।

73. मेरी सरकार द्वारा **'मुख्यमन्त्री सहारा योजना'** के अन्तर्गत गंभीर बीमारियों से ग्रसित 18,218 मरीज़ों को 61 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान

की गई है। इसके अतिरिक्त **'कैंसर केयर योजना'** के अन्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक 4,649 मरीज़ों के मुफ्त कीमोथैरेपी सैशन भी लगाए गए हैं।

74. मेरी सरकार **'राष्ट्रीय टी0बी0 उन्मूलन कार्यक्रम'** के अन्तर्गत राष्ट्रीय समय–सीमा से पूर्व, टी0बी0 को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। MDR-TB मरीज़ों को **'मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना'** के अन्तर्गत, 1,500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, तपेदिक रोग की समय पर जाँच एवं निदान हेतु 7 CB-NAAT मशीनें भी खरीदी गई है।

75. मेरी सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कृतसंकल्प है। इस कड़ी में आई0जी0एम0सी0 शिमला के न्यू ओ0पी0डी0 ब्लॉक का निर्माण कार्य 103 करोड़ 18 लाख रुपये की लागत से पूरा कर लिया गया है। अटल इन्स्टीट्यूट मेडिकल सुपर स्पैशियलिटी शिमला का निर्माण कार्य 218 करोड़ 12 लाख रुपये की अनुमानित लागत से मार्च, 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आई0जी0एम0सी0 शिमला में ट्रॉमा सैन्टर लेवल–। व डा0आर0पी0 जी0एम0सी0 टाण्डा में ट्रॉमा सैन्टर लेवल–।। का निर्माण कार्य लगभग 38 करोड़ रुपये की लागत से जून, 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।

76. प्रदेश में कोरोना महामारी में आशा कार्यकर्ताओं के अमूल्य योगदान के दृष्टिगत उन्हें दिए जा रहे अतिरिक्त मासिक मानदेय को अप्रैल, 2021 से **2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,750 रुपये प्रतिमाह** किया गया है।

77. **राज्य में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र के कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 की 870 सीटें, विभिन्न विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर स्तर की 309 सीटें तथा एम0डी0एस0 की 95 सीटें भरी गई हैं।** राज्य के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लगभग 17 करोड़ रुपये के

उपकरणों की खरीद की जा चुकी है जिनमें मेडिकल कॉलेज नाहन, चम्बा व टांडा में 128 Slice CT Scan की मशीनें भी शामिल हैं और लगभग 87 करोड़ रुपये की खरीद का कार्य प्रगति पर है।

78. मेरी सरकार ने मण्डी में 20 करोड़ रुपये की लागत से तथा सुंदरनगर में 10 करोड़ रुपये की लागत से 2 मातृ–शिशु अस्पतालों (MCH) को पूर्ण करके जनता को समर्पित किया है। इसके साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सर्वसुलभ बनाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 10 नए उप–स्वास्थ्य केन्द्र व 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 04 उप–स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 06 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को नागरिक अस्पतालों में स्तरोन्नत किया गया है। **प्रदेश के अस्पतालों के सुचारू संचालन हेतु 260 चिकित्सा अधिकारियों सहित विभिन्न श्रेणियों के 1,555 पदों का सृजन किया गया है। मेरी सरकार के कार्यकाल में लगभग 1,728 डॉक्टर तथा 1,781 पैरा मैडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है। इस समय प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों की कमी नहीं है।**

79. आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से मेरी सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान 20 लाख 71 हज़ार 416 रोगियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई। बहुविशेषज्ञता शिविरों के माध्यम से 29,119 रोगियों की स्वास्थ्य जाँच की गई। 20 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में उपलब्ध पंचकर्म सुविधा के माध्यम से 13,305 रोगी लाभान्वित हुए।

80. **'राष्ट्रीय आयुष मिशन'** के अन्तर्गत 97 आयुष हेल्थ व वैलनेस केन्द्र अधिसूचित किए गए हैं। इस वर्ष के दौरान 152 किसानों को औषधीय पौधों की खेती पर 37 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, **'आजादी का अमृत महोत्सव'** के अवसर पर **'आयुष**

आपके द्वार' कार्यक्रम के अन्तर्गत 652 किसानों को 6,614 औषधीय पौधों का वितरण किया गया है। कोविड–19 महामारी के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 83,650 live session के माध्यम से विभिन्न आयु समूहों के 7 लाख 9 हज़ार 234 प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं।

81. कोविड–19 के कारण पिछले 2 साल छात्र एवं शिक्षकों के लिए कठिनाइयों से भरे रहे हैं। मेरी सरकार द्वारा इस कठिन समय में शिक्षण संस्थानों को बंद किए जाने के दौरान शैक्षणिक गतिविधियों को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था '**हर–घर पाठशाला कार्यक्रम**' के अन्तर्गत की गई। शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से छात्रों का लगातार मूल्यांकन कर उनकी उपलब्धियों को ई–पी0टी0एम0 द्वारा उनके माता–पिता के साथ सांझा किया गया।

82. Teaching Learning Process में सुधार करने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा शिक्षण सत्र 2021–22 से शीतकालीन विद्यालयों की कक्षा तीसरी, पांचवीं व आठवीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं का संचालन नई **'राष्ट्रीय शिक्षा नीति'** के अनुरूप किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान कर 100 मेधावी छात्रों को छात्रवृति प्रदान करने के उद्देश्य से **'स्वर्ण जयन्ती मिडल मैरिट छात्रवृति योजना'** आरम्भ की गई है।

83. मेरी सरकार द्वारा 100 चिन्हित क्लस्टर विद्यालयों में बुनियादी ढांचे का विकास व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से **'स्वर्ण जयन्ती ज्ञानोदय संकुल श्रेष्ठ विद्यालय योजना (ज्ञानोदय)'** आरम्भ की गई है। इन क्लस्टर स्कूलों को 15 लाख रुपये प्रति क्लस्टर की दर से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

84. चालू वित्तीय वर्ष में **'अटल स्कूल वर्दी योजना'** के अन्तर्गत 11वीं व 12वीं कक्षा के 1 लाख 72 हज़ार 392 छात्रों को स्कूल वर्दी के दो सैट उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 9वीं व 10वीं कक्षा के 1 लाख 24 हज़ार 412 छात्रों को निःशुल्क पाठय पुस्तकें भी प्रदान की गई हैं।

85. मेरी सरकार शिक्षण संस्थानों के नवीनीकरण एवं गुणवत्ता उत्थान हेतु कृतसंकल्प है। चालू वित्तीय वर्ष में **'स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना'** के अन्तर्गत 68 उत्कृष्ट विद्यालयों को विद्यालय परिसर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 44 लाख रुपये प्रति संस्थान तथा 18 उत्कृष्ट महाविद्यालयों के लिए 75 लाख रुपये प्रति संस्थान स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 13 नई राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई हैं और 20 प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक, 10 माध्यमिक पाठशालाओं को उच्च माध्यमिक, 13 उच्च माध्यमिक पाठशालाओं को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत किया गया है।

86. मेरी सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को जे0ई0ई0–नीट प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने हेतु **'स्वर्ण जयन्ती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना'** आरम्भ की है। इसके अतिरिक्त, 10वीं कक्षा के 100 शीर्ष मेधावी विद्यार्थियों को व्यवसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए कोचिंग हेतु **'स्वर्ण जयन्ती सुपर 100 योजना'** भी आरम्भ की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

87. वर्तमान वित्तीय वर्ष में मध्याह्न भोजन कर्मियों के मासिक मानदेय में 300 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई है। राज्य के इन कर्मियों को हाईजीन किट प्रदान करने हेतु 1 करोड़ 93 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों में अंशकालीन मल्टीटास्क वर्कर्ज़ के 8000 पदों को भरने की स्वीकृत भी प्रदान की गई है।

88. कॉलेज कैडर तथा स्कूल कैडर में विभिन्न श्रेणियों के 1,066 शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नियमित किया गया है, एस0एम0सी0 व आई0टी0 शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है।

89. **मेरी सरकार ने प्रदेश में उच्चतर शिक्षा के विस्तार करने के उद्देश्य से एक और राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। मण्डी में 'सरदार पटेल विश्वविद्यालय' स्थापित करने हेतु विधेयक इस माननीय सदन द्वारा दिसम्बर, 2021 को पारित किया गया है।**

90. प्रदेश के युवाओं को गुणात्मक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु जिला कांगड़ा में राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, जिला बिलासपुर के बंदला में राजकीय हाईड्रो अभियांत्रिकी महाविद्यालय और जिला शिमला के कोटला–ज्यूरी में महात्मा गांधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अनुमोदित किए गए हैं। इन दोनों नए अभियांत्रिकी महाविद्यालयों तथा 02 नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जिला मण्डी के बागाचनोगी व बरोटी में कक्षाएं सत्र 2020–21 से आरम्भ कर दी गई हैं।

91. युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु मेरी सरकार द्वारा राज्य में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई0टी0आई0) की आधारिक संरचना का उन्नयन किया जा रहा है।

92. वर्तमान में केन्द्र प्रायोजित स्कीम (स्ट्राईव) के अन्तर्गत 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है और इन चयनित संस्थानों को 30 करोड़ 70 लाख 65 हज़ार रुपये की राशि, परियोजना अवधि के लिए आबंटित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 12 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

93. सभी प्रशिक्षण संस्थानों से लगभग 4,273 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में रोज़गार उपलब्ध करवाया गया है।

94. वरिष्ठ महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व हेतु राज्य में **'स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना'** आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के 1000 रुपये प्रति माह की दर से सामाजिक

सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना से लगभग 40,000 वरिष्ठ महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 6 लाख 35 हज़ार 375 पात्र व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रति माह प्रदान की जा रही है, जिस पर लगभग 929 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है। मेरी सरकार के कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 2 लाख 21 हज़ार 378 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं।

95. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों के पात्र व्यक्तियों को गृह निर्माण के अन्तर्गत नए मकान बनाने हेतु 1 लाख 50 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति की दर से अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में 4,565 मकान बनाने हेतु 68 करोड़ 48 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

96. **'बाल संरक्षण सेवा योजना'** के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में child care संस्थानों में देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले 1,413 बच्चों को प्रवेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मेरी सरकार द्वारा **'फोस्टर केयर योजना'** के अन्तर्गत इस वर्ष 24 बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चे की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

97. मेरी सरकार द्वारा **'मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना'** के अन्तर्गत बाल व बालिका आश्रमों में रह रहे 20 बच्चों को 10,000 रुपये की दर से वार्षिक छात्रवृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार की सहायता से देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को अस्थाई आश्रय प्रदान करने हेतु शिमला के ब्योलिया में एक **'खुला आश्रय'** स्थापित किया गया है।

98. मेरी सरकार महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। चालू वित्तीय वर्ष में **'मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना' व 'विधवा पुनर्विवाह योजना'** के अन्तर्गत 9 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 18,000 महिलाओं व बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त,

'बेटी है अनमोल योजना' के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 13 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से लगभग 4 करोड़ 68 लाख रुपये की राशि व्यय कर 13,084 लड़कियों को लाभान्वित किया गया है।

99. मेरी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 30 नवम्बर, 2021 तक **'प्रधानमंत्री मातृ–वंदना योजना'** के अन्तर्गत प्रथम किश्त में 28,239 महिलाओं को 2 करोड़ 82 लाख रुपये, द्वितीय किश्त में 28,112 महिलाओं को 5 करोड़ 62 लाख रुपये तथा तृतीय किश्त में 25,920 महिलाओं को 5 करोड़ 18 लाख रुपये की राशि उनके बैंक खातों में वितरित की है।

100. **'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना'** के अन्तर्गत बेसहारा लड़कियों की शादी हेतु उनके अभिभावकों को अनुदान के रूप में 51,000 रुपये देने का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 1,831 लड़कियां लाभान्वित हुई हैं। इसके अतिरिक्त, बी0पी0एल0 परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए 31,000 रुपये की अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए **'मुख्यमंत्री शगुन योजना'** आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत लगभग 8 करोड़ 83 लाख रुपये व्यय कर 2,849 लड़कियों को लाभान्वित किया गया है।

101. कोविड–19 महामारी के विरूद्ध लड़ाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं ने भी सकारात्मक भूमिका निभाई है। मेरी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायिका तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के मानदेय में बढ़ौतरी की है।

102. हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ–साथ वीरभूमि के रूप में भी जाना जाता है। यहां के जांबाज़ सपूत देश की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। मेरी सरकार प्रदेश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं, शौर्य पुरस्कार विजेताओं व उनके आश्रितों के कल्याण के प्रति संकल्पबद्ध है। चालू वित्त वर्ष में 60 वर्ष से अधिक

आयु के 1,380 पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं, जो किसी प्रकार की पैन्शन नहीं ले रहे हैं, 1,015 शौर्य पुरस्कार विजेताओं, युद्ध में शहीद व अपंग हुए सैनिकों के 62 आश्रितों, युद्ध जागीर के 414 लाभार्थियों, सेवाकाल के दौरान मृत 14 सैनिकों के आश्रितों तथा पूर्व सैनिकों के राहत एवं पुनर्वास हेतु 14 करोड़ 38 लाख 10 हज़ार रुपये की धनराशि वितरित की गई है।

103. मेरी सरकार वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानियों व उनके आश्रितों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। वर्तमान में **'हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान राशि योजना'** के अन्तर्गत 20 जीवित स्वतन्त्रता सेनानियों व 380 स्वर्गीय स्वतन्त्रता सेनानियों की पत्नियों को 15,000 रुपये प्रतिमाह की दर से सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। इन स्वतन्त्रता सेनानियों की 13 अविवाहित पुत्रियों को भी 10,000 रुपये प्रतिमाह की दर से सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2021 तक लगभग 5 करोड़ 76 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गई है।

104. प्रदेश में स्वतन्त्रता सेनानियों की पुत्रियों को 51,000 रुपये व पौत्रियों को 21,000 रुपये की अनुग्रह राशि उनके विवाह हेतु प्रदान की जा रही है। दिसम्बर, 2021 तक स्वतन्त्रता सेनानियों की 37 पौत्रियों को उनके विवाह हेतु राशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त, स्वतन्त्रता सेनानियों की मृत्यु पर 25,000 रुपये व उनकी पत्नियों की मृत्यु पर 20,000 रुपये की राशि उनके परिवारजनों को दाह संस्कार हेतु प्रदान की जा रही है। इसके लिए दिसम्बर, 2021 तक लगभग 3 लाख 95 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की गई है।

105. वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान मीसा/डी0आई0आर0/दण्ड प्रक्रिया संहिता (सी0आर0पी0सी) के अधीन राजनीतिक व सामाजिक कारणों से कारावास व पुलिस स्टेशनों में

निरूद्ध रहे व्यक्तियों के लिए मेरी सरकार ने **'हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना'** आरम्भ की है। इसके अन्तर्गत 1 से 15 दिनों तक कारावास व पुलिस स्टेशनों में निरूद्ध रहे व्यक्तियों को 8000 व 15 दिनों से अधिक समय तक निरूद्ध रहे व्यक्तियों को 12,000 रुपये प्रतिमाह की दर से सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। दिसम्बर, 2021 तक 84 व्यक्तियों को लगभग 96 लाख 68 हज़ार रुपये की राशि वितरित की गई है।

106. कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न विकट आर्थिक परिस्थितियों में **गरीब परिवारों को 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के अन्तर्गत मई से नवम्बर, 2021 तक 02 किलो चावल व 03 किलो गंदम प्रति व्यक्ति निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। इस योजना को अब मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया है।**

107. मेरी सरकार द्वारा अन्तर्राज्य राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी व **'एक राष्ट्र एक राशन–कार्ड योजना'** के अन्तर्गत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी का शुभारम्भ किया गया है। अब उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दुकान से पात्रता अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त, राज्य में सभी उचित मूल्य की दुकानों के स्वचालन हेतु पॉस मशीनों की स्थापना की गई है।

108. मेरी सरकार राज्य की गृहिणियों को धुंआरहित ईंधन प्रदान करने, महिला सशक्तिकरण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वचनबद्ध है। **इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आरम्भ की गई 'मुख्यमन्त्री गृहिणी सुविधा योजना' के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 3 लाख 24 हज़ार पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं।** वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान मुफ्त रिफिल की सुविधा सहित 17,919 घरेलू गैस कनैक्शन आबंटित किए गए हैं।

109. हिमालयी क्षेत्र होने के कारण हमारा प्रदेश जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है। मेरी सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए **'राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष'** के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 30,880 किसानों को Climate changeAdaptation पर प्रशिक्षण प्रदान किया है।

110. राज्य में लगभग 0.5 टन से 5 टन कचरे के निपटान के लिए 10 solid waste प्रबन्धन पायलट परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने **'नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़'** के अन्तर्गत 4 करोड़ 48 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। वर्तमान में लगभग 51 लाख रुपये की राशि शहरी स्थानीय निकायों को जारी कर दी गई है।

111. मेरी सरकार द्वारा राज्य में **'मॉडल इको विलेज योजना'** लागू की जा रही है जिसके अन्तर्गत कम प्रभाव वाली जीवन शैली विकसित कर ecological footprint को 50 प्रतिशत स्तर तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसम्बर माह तक इस योजना के अन्तर्गत 15 गांवों को शामिल कर 1 करोड़ 84 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

112. मेरी सरकार प्रदेश के युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में खेल प्रोत्साहन के प्रयासों को समन्वित करने, सरल व कारगर बनाने, खेल संस्कृति व खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ाने के उद्देश्य से इस वर्ष **'हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयन्ती खेल नीति'** अधिसूचित की गई है। यह नीति खेलों के ढांचागत विकास, प्रतिभा खोज, खेल प्रशिक्षण एवं खेल प्रतिभागियों के प्रयासों में, सभी हितधारकों के संसाधनों को सम्मिलित कर व सभी के सक्रिय योगदान से गति प्रदान करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने जिला सिरमौर के माजरा में सिंथैटिक हॉकी टर्फ बिछाने, जिला कांगड़ा के नूरपुर में सिंथैटिक एथलैटिक रनिंग ट्रैक

बनाने और जिला सोलन, जिला मण्डी के सुन्दरनगर, जिला ऊना के बंगाणा, जिला बिलासपुर के घुमारवीं व जिला कांगड़ा के परागपुर में बहुउद्देश्यीय खेल हॉल के निर्माण हेतु 35 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

113. उभरती खेल प्रतिभाओं का राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना राज्य के लिए गौरव का विषय है। प्रदेश के 2 प्रतिभावान खिलाड़ियों सर्वश्री वरूण व निशाद ने टोक्यो ओलम्पिक–2020 (हॉकी) व पैरा–ओलम्पिक–2020 (एथलैटिक ऊंची कूद) में पदक प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। मेरी सरकार ने इन दोनों प्रतिभावान ओलम्पियन खिलाड़ियों को 1–1 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान कर उन्हें रोज़गार की पेशकश की है।

114. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां प्रदान करने हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान 180 खिलाड़ियों को रोज़गार के लिए संस्तुत किया गया है।

115. प्रदेश के राजस्व सृजन में आबकारी एवं कराधान का महत्वपूर्ण योगदान है। मेरी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मौजूदा और सम्भावित करदाताओं, उपभोक्ताओं, सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों के कर सम्बन्धी संशयों एवं प्रश्नों के समयबद्ध समाधान के लिए **'टैक्स हाट कार्यक्रम'** आरम्भ किया है। इसके अतिरिक्त, व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निदान हेतु एक **'व्यापारी सुविधा केन्द्र'** स्थापित किया गया है।

116. मेरी सरकार द्वारा व्यावसायिक संचालन हेतु बनाई गई बेहतर रणनीति के फलस्वरूप राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में पहली तिमाही में 109 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 29 प्रतिशत व तीसरी तिमाही में 8 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित की है। इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष में कोविड–19 के प्रभाव के बावजूद लगभग 6,226 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित किया गया है, जोकि गत वित्तीय वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है।

117. राज्य में पुराने कर सम्बन्धी मामलों के निपटान हेतु आरम्भ की गई **'हिमाचल प्रदेश विरासत मामले समाधान योजना'** के अन्तर्गत 14,814 पुराने कर मामलों का निपटारा कर लगभग 393 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के मामलों के निपटारे हेतु **'हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती विरासत मामले समाधान योजना'** 27 दिसम्बर, 2021 को अधिसूचित की गई है।

118. मेरी सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के चहुँमुखी विकास हेतु प्रयत्नशील है। विभिन्न विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों के अतिरिक्त बाहरी सहायता से चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 9,897 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत की 13 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, 1,168 करोड़ रुपये की **'हिमाचल प्रदेश जल आपूर्ति और सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम'** और 756 करोड़ रुपये की **'हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति'** परियोजनाओं के ऋण समझौते किए गए हैं।

119. मेरी सरकार राज्य के पुलिस कर्मचारियों की मोबिलिटी, आधारभूत संरचना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अत्यन्त गौरव का विषय है कि हिमाचल पुलिस **'प्रेसिडेंट कलर्स'** प्राप्त करने वाला देश का 8वां पुलिस बल बना है। हिमाचल प्रदेश ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सी0सी0टी0एन0एस0) की कार्यपद्धति में पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश पुलिस बल को पासपोर्ट सत्यापन रिपोर्टों में प्रथम स्थान और राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस में रजत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

120. प्रदेश में फारेंसिक सेवाओं के उन्नयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में बद्दी, नूरपुर व बिलासपुर में 03 जिला फारेंसिक इकाइयां स्थापित कर क्रियाशील कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय फारेंसिक विज्ञान

प्रयोगशाला, धर्मशाला में डी0एन0ए0 और साइबर ब्लॉक का निर्माण किया गया है।

121. मेरी सरकार द्वारा कैदियों की देख–रेख और पुनर्वासन के उद्देश्य से **'Wages Earning Scheme'** और **'हर हाथ को काम'** योजनाएं चलाई जा रही हैं। कोरोना महामारी के दौरान कैदियों द्वारा बनाए गए मास्क एवं सेनिटाइज़र की विभिन्न विभागों को आपूर्ति की गई। इसके अतिरिक्त, कैदियों को फाइन आर्टस में प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा समय–समय पर उनके कार्यों को राज्य के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

122. प्रदेश के वनों व रिहायशी क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं से होने वाली जान–माल की हानि को रोकना अति आवश्यक है। इस कड़ी में चालू वित्तीय वर्ष में 03 अग्निशमन चौकियां, शिमला के टिक्कर तथा जिला किन्नौर के सांगला व भावानगर में स्थापित की गई हैं। अग्निशमन सेवाओं की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु 17 नये वाहनों को खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, अग्निशमन विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 733 करोड़ रुपये की संपत्ति को नष्ट होने से बचाया गया है।

123. मेरी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में जनहित में 07 उप–मण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालयों, 04 तहसीलों, 10 उप–तहसीलों तथा 11 नए पटवार वृतों का सृजन किया है।

124. मेरी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में पटवारियों के 881 पदों को भरा है और राजस्व विभाग में कार्यरत नम्बरदारो का मानदेय बढ़ाकर **2,300 रुपये** तथा पटवार सर्कलों में तैनात अंशकालिक श्रमिकों का मानदेय बढ़ाकर **4,100 रुपये प्रतिमाह** कर दिया है।

125. **राजस्व रिकॉर्ड में हर गांव (आबादी या आबादी देह) में रहने वाले कब्जा धारकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान कर सम्पत्ति कार्ड जारी करने के**

उद्देश्य से 'स्वामित्व योजना' कार्यान्वित की जा रही है। प्रदेश में कुल 15,495 आबादी देह/गांवों को लाभान्वित कर स्वामित्व प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम में संशोधन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जिला हमीरपुर में पायलट आधार पर Drones के माध्यम से कार्य चल रहा है और यह योजना अगले 1 वर्ष में सभी जिलों में लागू करने का लक्ष्य है।

126. हिमाचल प्रदेश एक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है इसलिए प्रदेश में केन्द्र सरकार की सहायता से **'National Earthquake Risk Mitigation'** परियोजना आरम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जानी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, फ्रांसीसी विकास एजेंसी ने लगभग 800 करोड़ रुपये लागत की बाह्य वित्त पोषित **'Disaster Risk ReductionAnd Preparedness'** के लिए सहमति प्रदान की है।

127. इस वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय जनजातीय कार्य मन्त्रालय द्वारा प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के तीव्र विकास एवं अनूसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु 15 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। इसके अतिरिक्त, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए **'जनजातीय अनुसंधान संस्थान को समर्थन'** योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 6 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

128. मेरी सरकार आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर जिला किन्नौर के रिकाँगपिओ में राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य व शिल्प महोत्सव और स्पिति के काजा में समुद्रतल से 12 हज़ार 40 फुट की ऊंचाई पर प्रथम महिला आइस हॉकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु बधाई की पात्र है।

129. मेरी सरकार कर्मचारियों को अधिक कुशल एवं कर्तव्यपरायण बनाने के लिए उनके कौशल एवं क्षमता का विकास करने हेतु संकल्पबद्ध है। इस

कड़ी में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान द्वारा 3,709 अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

130. सरकारी कार्यालयों में किए जाने वाले कार्य के त्वरित निष्पादन, इसकी दक्षता एवं पारदर्शिता, प्रतिकूल परिस्थितियों में सरकारी कार्यालयों के सुचारू संचालन एवं कागज़ के प्रयोग को कम करने के लिए, ई–ऑफिस क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में सचिवालय, उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक कार्यालयों, 46 निदेशालयों तथा 30 अन्य कार्यालयों में **'ई–ऑफिस'** आरम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, विभागों से सम्बन्धित योजनाओं व परियोजनाओं के मूल्याकंन एवं निगरानी हेतु **'सी0एम0 डेशबोर्ड'** भी विकसित किया गया है।

131. प्रदेश की जनता के प्रति उत्तरदायी प्रशासन सुनिशिचित करने और उनकी शिकायतों का समयबद्ध एवं त्वरित समाधान घर बैठे करवाने के उद्देश्य से **'मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन–1100'** आरम्भ की गई है। **इस हेल्पलाइन पर जनवरी, 2022 तक प्राप्त 3 लाख से अधिक शिकायतों में से 2 लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। यह हेल्पलाइन कोविड–19 रोगियों को स्वास्थ्य व उपचार सम्बन्धी जानकारी एवं आपातकालीन स्थितियों में फंसे नागरिकों को सहायता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुई है। इसके अतिरिक्त, नशा पीड़ित रोगियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु 'नशा निवारण हेल्पलाइन' को भी इस हेल्पलाइन के साथ जोड़ा गया है।**

132. जन समस्याओं के शीघ्र निपटारे हेतु केन्द्रीय पोर्टल 'CPGRAMS' को राज्य पोर्टल **'ई–समाधान'** के साथ एकीकृत किया गया है। इससे 'CPGRAMS' पर हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित शिकायतें सीधी राज्य पोर्टल पर प्राप्त हो रही हैं जिनका निपटारा शीघ्र ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। सभी उपायुक्त कार्यालयों में स्थापित सुगम केन्द्रों पर ई–समाधान प्रणाली के अन्तर्गत शिकायत दर्ज करने हेतु एक विशेष

काउंटर स्थापित किया गया है। हिमाचल भवन, चंडीगढ़ तथा हिमाचल सदन, नई दिल्ली में भी नए शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। जन शिकायत निवारण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य, जिला एवं उप–मण्डल स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है।

133. सरकारी कार्यालयों में आने के बजाय नागरिकों को उनके घर द्वार पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आरम्भ किए गए **'हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल'** के माध्यम से 96 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसे भारत सरकार के **'उमंग पोर्टल'** के साथ एकीकृत किया जा रहा है। **'सूचना का अधिकार अधिनियम'** के अन्तर्गत भी आवेदक इलैक्ट्रॉनिक रूप से घर द्वार पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। **'लोक सेवा गारंटी अधिनियम'** के तहत 253 लोक सेवाओं और बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान के तहत 80 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है।

134. राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी से बचाव के लिए **'फोक मीडिया'** इकाइयों के माध्यम से 2,949 **'ड्रामा शो'** आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, इस महामारी से ग्रसित रोगियों के लिए **'होम आइसोलेशन'** पुस्तिका भी प्रकाशित की गई, जिसमें आपात स्थिति में महत्वपूर्ण दूरभाष नंबरों के साथ–साथ सावधानियों और घरेलू उपचारों का विवरण दिया गया है।

135. मेरी सरकार ने प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रत्यायन एवं मान्यता प्राप्त प्रत्रकारों को पी0वी0सी0 डिजिटल स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त इन पत्रकारों को **'समूह दुर्घटना बीमा कवरेज योजना'** के अन्तर्गत भी लाया गया है।

136. विकास कार्यों के लक्ष्यों को हासिल करने में कर्मचारियों की भूमिका के दृष्टिगत राज्य में कार्यरत कर्मचारियों का वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2016 से संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आउटसोर्स

कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान माह के सातवें दिन तक करने बारे दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

137. विभिन्न विभागों में कार्यरत मज़दूरों की न्यूनतम दिहाड़ी प्रचलित दर 275–572 रुपये से बढ़ाकर 300–597 रुपये तथा अंशकालीन कामगारों की पारिश्रमिक दर को **34 रुपये 50 पैसा प्रति घण्टा** से **बढ़ाकर 38 रुपये प्रति घण्टा** किया गया है। इसके अतिरिक्त जनजातीय भत्ते को **450 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये प्रतिमाह** और शीतकालीन भत्ते को **300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह** किया गया है।

138. प्रदेश सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2021 तक राज्य के विभिन्न विभागों में अलग–अलग श्रेणियों के 1,754 पद सृजित करने और 5000 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों में 30 सितम्बर, 2021 को 2 साल का कार्यकाल पूर्ण कर चुके अनुबन्ध कर्मचारियों तथा इस अवधि तक 4 साल की लगातार सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतन भोगी/कंटिजैंट पेड वर्कर्स को नियमित करने के निर्देश 28 दिसम्बर, 2021 को जारी किए गए हैं।

139. हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति का विनियमन करने के लिए मेरी सरकार द्वारा 46 वर्षों के उपरान्त दिनांक 19 जनवरी, 2022 को हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (समयपूर्व सेवानिवृत्ति) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मेरी सरकार ने समय–समय पर जारी नियमों एवं निर्देशों को समेकित कर 26 वर्षों के उपरान्त कार्मिक मामलों को निष्पक्ष रूप से निपटाने में उपयोगी **'हैंडबुक ऑन परसोनल मैटर्स'** दिसम्बर, 2021 में जारी की है।

140. मेरी सरकार द्वारा गत 3 वर्षों में विभिन्न विभागों में अलग–अलग श्रेणियों के कुल 23,931 पदों तथा विभिन्न बोर्ड/निगम/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत निकाय/प्राधिकरण एवं विश्वविद्यालयों में विभिन्न

श्रेणियों के 5,546 पदों पर नियुक्तियां की गई। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 805 पदों और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के लगभग 5,349 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष मेरी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि राज्य के लोगों के हित और प्रदेश को विकास एवं खुशहाली की राह पर आगे ले जाने के लिए मेरी सरकार के प्रयासों को आप अपना पूर्ण सहयोग देंगे। मैं यह भी आशा करता हूं कि आप सभी इस माननीय सदन की उच्च परम्पराओं को बनाए रखेंगे।

माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी के प्रसन्न और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। मेरी सरकार की गतिविधियां आपके समक्ष रखने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान करने पर भी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं।

जय हिन्द, जय हिमाचल।

राष्ट्रगान गाया गया।

(माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

उपाध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 24 फरवरी, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 23 फरवरी, 2022 **सचिव।**